NT>
Title: General discussion on the Budget (General) for 1999-2000, Supplementary Demands for Grants for 1998-99 and Demands for Excess Grants for 1996-97.

17.58 hrs.

सभापति महोदयः मद संख्या २३ से २५ एक साथ ली जाएंगी।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि सदन का समय आठ बजे तक है।

Motions moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1999 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demand Nos.:

1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 and 103."

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the Presidnet out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants during the year ended 31st day of March, 1997, in respect of the following demands entered in the second column thereof:

Demand Nos. 8, 14, 24, 56, 62, 82 and 83."

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय बजट पर कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF TOURISM (SHRI ANANTH KUMAR): Sir, the hon. Finance Minister is replying to a debate in the Rajya Sabha. I am representing him here and I am taking all the notes... (Interruptions)

Cabinet Minister should have been present here... (Interruptions)

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Shri Baalu, the hon. Minister is in the Rajya Sabha for replying to a debate.

श्री बलराम जाखड़ : यह बजट २०वीं शताब्दी का अंतिम बजट है। अतः यह आने वाली मिलिनियम की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे अधिक विवेकपूर्ण, दूरदर्शितापूर्ण, दिशा-निर्देशित और व्यावहारिक होना चाहिए था, जो यह नहीं है। १९९८-९९ का बजट रखते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं छः महीने में ही इकोनमी को किक स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं किक स्टार्ट तो क्या वह धक्का स्टार्ट भी नहीं हुई। यह बजट ऐसे वातावरण में प्रस्तुत किया गया है जब चारों ओर मंदी का वातावरण है, विश्व व्यापार भी नीचे आ गया है। चारों तरफ रिसैशन का वातावरण व्याप्त है। साथ ही अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण होने जा रहा है। पोखरन विस्फोट से उत्पन्न आर्थिक समस्याएं भी हमारे सामने हैं। विश्व के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए भी विचार-विमर्श करना, जिसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इन बातों को देखते हुए भारत इनसे अछूता नहीं रह सकता कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा बजट क्या कहता है।

18.00 hrs.

वैसे भी देखा जाए:

The present Budget is presented in the context of global economic recession.

इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसमें से निकलें। हालांकि थोड़ा बहुत ईस्ट एशिया में वातावरण ठीक हुआ है लेकिन फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ब्राजील में जो कुछ हो रहा है, वह इस बात का द्योतक है कि संसार भर में इकॉनोमिक स्टैबिलिटी खतरे में है। डौमैस्टिक सीन भी उत्साह वर्धक नहीं है। १९९८-९९ में हमारी ग्रोथ जी.डी.पी. ५.८ प्रतिशत बताई गई है। वह इसलिए है क्योंकि कृषि उत्पादन अच्छा हुआ है। सिर्फ इसी वजह से है। इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस नहीं, ये सब ऐसे सैक्टर्स रहे हैं और नैगेटिव ग्रोथ एक्सपोर्ट की हो गई है। इसे देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेड का भी घपला दुगुना हो गया है। इस संदर्भ में अनेक कमेटियां बनाई गई हैं कि किस तरीके से वैरियस कमिटमैन्टस को टैकल किया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी इच्छा शक्ति उनको टैकल करने की है या नहीं और सरकार की कैपेसिटी उसको टैकल करने की है या नहीं। पैसा लगाने वालों में विश्वास-हीनता है। इंडस्ट्रियल रिसैशन भी है। इसे उत्साह वर्धक किया जाए। देखने की बात है कि करैक्ट एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएट इंटरवैंशन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से हो, तभी यह बात बनती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर भारत के प्रतिकूल है। देश की आर्थिक दशा निराशाजनक नजर आती है। इसमें देखने की बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं।

देश में जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? किस प्रकार से हम उन्हें रोजगार दिलवाएंगे और गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे कम करेंगे? ४० प्रतिशत जनता आज गरीबी रेखा के नीचे हो गई है, इसका क्या कारण है? इस पर हमें विचार करना होगा। इसके लिए इस बजट में क्या किया गया है, वह भी मुझे आशाजनक नज़र नहीं आ रहा है। १९९८-९९ के बजट में रेवेन्यू जो मेजर फोकस था, उसकी एडीशनल रेवेन्यू डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट टैक्सेज में १९९९-२००० के बजट में ९३३४ करोड़ रुपये टोटल इंक्रीज थी, टैक्स रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले २२८२८ करोड़ रुपये है। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस घपले को कैसे पूरा किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। बजट के टोटल प्लान एक्सपेंडिचर में पांच प्रतिशत की कमी आई है। सैन्ट्रल प्लान को भी छोटा कर दिया गया है।

Capital expenditure has been compressed. This is true with the budgetary support as well. Even the outlay on rural development programmes has been cut by 5.5 per cent less than initially planned.

यह भी सोचने की बात है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। बजट सरकार के हाथ में अत्यधिक प्रभावी और सक्षम साधन होता है जिससे वर्तमान समस्याओं को हल किया जा सके और आगे के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके। आकांक्षाओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है किंतु तत्कालीन समस्याओं का समाधान और भविष्य की समस्याओं का समाधान करने हेतु इसमें कोई सहारा हमारे पास नहीं है, इसलिए यह बजट मुझे सूझबूझहीन और दिशाहीन नज़र आता है। बजट समूचे प्रारूप में किसी आर्थिक क्षेत्र, उद्योग आदि को राहत और लाभ देने की जरूरत होनी चाहिए लेकिन व्यापकता और समूचे आर्थिक ढांचे में अपना दिशा-निर्देशन कहीं नहीं मिल रहा है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

Hope triumphs over realism.

हम दुनिया में आकांक्षाएं कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। आपने 'मुंगेरी लाल के सपने' सीरियल देखा होगा, उसी प्रकार से यह सरकार भी मुंगेरी लाल के सपने लेने में लगी हुई है। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे रिवाइज्ड एस्टीमैटस क्या हैं, बजट एस्टीमैटस क्या हैं, उसमें अंतर करके ऐसा आवरण ओढ़ा दिया गया है जिसमें असलियत नज़र नहीं आती है, सिर्फ धोखा ही धोखा है।

इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है।

Hope triumphs over realism in the expenditure figures as well. Between 1997-98 and 1998-99 (both Revised Estimates), Revenue Expenditure (which, roughly speaking, is the non-productive part of Government spending) increased by a little less than 20 per cent. By some magic, the order of increase will be less than 9 per cent the coming year, comparing the Revised Estimates of 1998-99 to the Budget Estimates of 1999-2000.

इस फर्क को भी आपको देखना होगा। आप नौ प्रतिशत की बात कहते हैं और २० प्रतिशत की बात कहते हैं, लेकिन इसको आप कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में भी आपको देखना होगा।

In absolute terms, this means that while the Government spent Rs.35,939 crore more in 1998-99 compared to 1997-98 on salaries, establishment costs etc., in 1999-2000 the annual increase will be only Rs. 18,848 crore.

कहा गया है कि सचिवों की संख्या को कम कर दिया जाएगा, इससे आप कितने खर्च को कम कर सकेंगे, इस बारे में आपने कोई विवरण नहीं दिया है, कोई प्लान नहीं दिया है। इन समस्याओं का हमारे पास कोई समाधान नहीं है।

जहां तक कृषि की बात है, कहा गया है कि हमने पिछले वर्षों के मुकाबले ३४ प्रतिशत राशि ज्यादा दी है, लेकिन देखने से पता चलता है कि कितना बड़ा आडम्बर रचाया गया है कि इस बात को कहने का। इस बारे में मैं आपको आंकड़े देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलायड एक्टिविटीज में १९९८-९९ में ३,८६४ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी और अब १९९९-२००० में २,७७७ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इन्फलेशन को देखें तो तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत हो गया है। इतना होने

पर भी कहते हैं कि हमने ३४ प्रतिशत राशि बढ़ा दी है। इससे बड़ी विडम्बना और कोई नहीं हो सकती है। कृषि हमारे देश के विकास का आधार है और ५.८ प्रतिशत हमारा

GDP

ग्रोथ रेट है। जहां तक रूरल डवेलपमेंट की बात है, इसमें भी कमी आई है। १९९८-९९ में ८१८२ करोड़ रुपए, १९९९-२००० में ७,८४२ करोड़ रुपए की व्यवस्था, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक हजार करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। इर्रिगेशन में भी ३७४ करोड़ रुपए के स्थान पर ३४८ करोड़ रुपए का प्रावधान, एनर्जी में तीस हजार के स्थान पर २७ हजार की व्यवस्था, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रगति करना चाहते हैं। पंचवर्षीय योजना में भी कृषि के विकास की सर्वोच्च वरीयता देने की बात कही गई है, लेकिन बजट में कृषि के लिए प्रावधान कम किया गया है। पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेंट का पैसा खर्च नहीं हुआ । मैं पूछना चाहता हूं, यह पैसा क्यों खर्च नहीं किया गया? इसका जवाब भी इनके पास नहीं है। आंखों में धूल झौंकने का काम किया गया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया गया है। कृषि के सिंचाई साधनों के लिए भी एक पैसा आवंटित नहीं किया गया है। कहते हैं कि हमने जरूर रखा है, लेकिन न अनुदान रखा है और न अन्य कोई व्यवस्था की गई है। कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ायेंगे, सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ायेंगे, लेकिन जो व्यवस्था की गई है, उससे नहीं लगता है कि इस दिशा में कोई काम हो पाएगा। डैम्स के निर्माण कार्य को बढ़ाने की दिशा में कोई प्रावधान नहीं है। मैंने अपने समय में कहा था कि सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति कर सकतेहैं, जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं, जमीन को क्षार होने से बचा सकते हैं, वाटर-लोगिंग से बचा सकते हैं और हमने इर्रिगेशन के लिए ९० प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की थी। इस में ७५ प्रतिशत हरिजनों के लिए व्यवस्था की गई थी।

उसमें कहीं एक पैसे का आबंटन नहीं किया गया है, वह पैसा कहां गया, इसका कोई जिक्र नहीं है। आप किस तरह से बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं। जो भी नई-नई स्कीम्स चल रही हैं, नहरें लगानी हैं, उनके कमांड एरिया पर हमने पहले ध्यान नहीं दिया। दुनिया भर में सबसे बड़ी नहर हमारी राजस्थान कैनाल है, जिसको हम आज कल इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। उसके आगे के क्षेत्र को देख लीजिए, वहां लाखों एकड़ जमीन पानी में दब गई है। वहां झील बनी हुई है लेकिन उसके विकास के लिए कोई पैसा नहीं रखा। गांव उजड़ गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, उत्पादन बंद हो गया है, उसके लिए कुछ नहीं रखा। उसको हम किस तरीके से रिक्लेम करेंगे। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, जोकि प्रेक्टीकल है, जो मैंने अपने हिसाब से किया, आप इसको किस तरह से रोकेंगे। कृषि पर आधारित उद्योगों का कहीं जिक्र नहीं है। हमने एक एग्रो बिजनेस कस्टोडियन बनाया था, उसके लिए कोई पैसा नहीं है और न ही इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप बढ़ती हुई आबादी के लिए रोजगार कैसे देंगे? रोज डकैतियां पड़ती हैं, कत्ल होते हैं, चोरिया होती हैं, शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही है, आप इनका निराकरण कैसे करेंगे? जब तक इस बारे में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप नाम बदल देते हैं। आपने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल कर ग्राम समृद्धि योजना और इंदिरा आवास योजना का नाम ग्राम समृद्धि योजना कर दिया। कल आप कहेंगे कि भारतवर्ष का नाम हम आर्यव्रत रखेंगे। मेरा कहना है कि जो जिसका नाम है वही रहने दो। आप बिना मतलब नाम बदल कर अनुचित काम करते हैं, आप सार्थक काम कीजिए।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप सार्थकता पर भरोसा करिए, नामों का अदल-बदल करके क्यों इंसल्ट करवाना चाहते हैं। इन्होंने ट्रेक्टर पर डयूटी बढ़ाई। ३५ हार्स पावर के ऊपर के ट्रेक्टरों पर डयूटी बढ़ाई। जो किसान पहले से मर रहा है आप उस पर और बोझ लाद रहे हैं। आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कितने मरे, पंजाब और हरियाणा में कितने किसानों ने आत्महत्या की, क्या कोई गिनती है? इनके लिए थोड़ा सा तो सोचें। उनकी फसल तबाह हो गई, सारा कुछ चौपट हो गया लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हम इंश्योरेंस पालिसी की योजना लाएंगे। यहां कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि आ जाएंगी, आ रही हैं, यह सुनते-सुनते जिन्दगी ने दम तोड़ दिया। आप किस तरीके से करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? अगर काम करना है तो बताइए कि कब और किस तरह से ला रहे हैं। 'माना कि तवाक्कुल न करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक,' यही मुझे नजर आता है। किसान तो मर रहा है, आप उसके लिए कब सोचेंगे? हमने उसके लिए कुछ किया था। उसका उद्धार आगे आप करो। हमने जो किया, आप उससे आगे करो। हमने छोटी सी पगडंडी बनाई, आप उस पर सड़क बना दीजिए। ... (व्यवधान) रास्ता बना दिया, अब आप आगे निकल जाइए। सड़क खोल दी, फाटक खोल दिया, अब आप आगे बढ़ जाओ। मेरा कहना है कि इनडिविजुअल पालिसी बनाएं, इस पर हमें किस तरह से काम करना है, यह देखें। मैं किसान की बात कर रहा हूं। ट्रेक्टर की कीमत ६,००० रुपए से ९,००० तक बढ़ जाएगी। भारत में ६० प्रतिशत ट्रेक्टर ३५ हार्स पावर के ऊपर हैं। जहां अन्न उत्पादन होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या जहां भी होता है,

आप देखिये, आप क्यों किसानों को मारना चाहते हैं। कुछ उनके बारे में सोचें कि वे हमारे किसान हैं। कुछ तो आप किसानों के लिए करिये। कपास की फसल नष्ट होने से किसान कठिनाई में पड़ जाएगा। आप बड़े ट्रेक्टरों पर बढ़ाई गयी एक्साइज डयूटी को फौरन वापस करिये, यह मेरी मांग है। किसान डीजल लेता है, आपने डीजल की कीमत बढ़ा दी, फिर आप कहते हैं कि आप किसानों की मदद कर रहे हैं। उसकी कपास, मूंगफली, सोयाबीन की खेती तबाह हो गयी। आपकी तरफ से उसको पैसा नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। आपने नाबाड में कुछ पैसा बढ़ाया। किसान ने ४०-५० प्रतिशत ब्याज पर पैसा लिया लेकिन जब वह पैसा नहीं दे पाया तो वह मर गया, आत्महत्या कर ली, फांसी उसने खा ली। मैंने खुद लाश देखी हैं। किसान के बच्चे तड़प रहे थे, उसकी विधवा भूखी बैठी थी, उसके बच्चे बेसहारा हो गये हैं।

हमारे देश में कृषि पर ६५ प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट ५०-५५ प्रतिशत से २४ प्रतिशत पर आ गयी है। सबसे बड़ी समस्या छोटे किसान की है। आपको उनके लिए नये रोजगार सृजित करने चाहिए। आपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नहीं रखा। हमारी कितनी पैरिशेबल चीजों का विनाश होता है। दुनिया में हमारा फलों में पहला नम्बर है। सब्जियों में हम चीन का मुकाबला करते हैं और दूध में हम अपने देश को अमरीका के मुकाबले में ले आए हैं। आप किसानों को ईनाम देने के बजाए उनको दंडित क्यों करते हैं। उनके लिए पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, उनके लिए न ग्रेडिंग है, न पैकेजिंग है, न प्रोसेसिंग है, न फोरवर्डिंग है, न ट्रांसपोर्टेशन है, न स्टोरेज फैसिलिटी का प्रबंध है। बाहर के देशों में ४५-५० प्रतिशत सब्जियों और फलों को डिब्बाबंद कर दिया जाता है, यहां पर तो २५-३० प्रतिशत नष्ट हो जाते हैं। यहां पर तो प्याज ४०-५० रुपये किलो तक हो जाता है। आज हालत क्या है? सवा या डेढ़ रुपये किलो प्याज बिक रही है, उनकी मजदूरी पूरी नहीं होती है। किसान की मुसीबत है। वह पैदा करे तब भी मरता है, न करे तब भी मरता है। वह मरने के लिए बना है। उसके लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया है। आज किसानों को हमदर्दी की आवश्यकता है। आज गांव में ७४ प्रतिशत लोग रहते हैं। उनकी जमीनें छोटी-छोटी हो गयी हैं, लेकिन उद्योग का कोई चांस नहीं है। हम कृषि में तो मुकाबला कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई में हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। शहरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और तीन-तीन हजार रुपया मासिक ट्यूशन फीस देते हैं, उनका मुकाबला गांव के बच्चे नहीं कर पाते हैं। कुछ एग्रो-बेस कंसोरटियम बनाकर उनके लिए नौकरी का इंतजाम शुरू कर दो, टैक्नीकल काम उन्हें सिखा दो, वह भी आप नहीं सिखाते हैं।

आप कोओपरेटिव्ज की बात करते हैं। आपने उसके लिए बहुत अच्छा बिल बनाया है। लेकिन आप कहते हैं कि कोओपरेटिव्ज का काम स्टेट करें, हम कुछ नहीं करेंगे। आप कोओपरेटिव्ज को तबाह करना चाहते हैं।

मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा कि ३० वर्ष पुराना इन्कम-टैक्स कोओपरेटिव्ज पर वसूल किया जा रहा है। यह कभी आपने सुना है। आप क्या करना चाहते हैं? मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जरा इस बारे में सोचें। इस तरीके से काम नहीं होता है। नैफेड को ८४ करोड़ रुपया देना है। उसका इलेक्शन हो गया, इन्होंने जो नाम रखा था वह जीता नहीं, हार गया। आज उसको तबाह करने पर आप तुले हैं। आप क्या करना चाहते हैं?

क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? आपने उनसे सारे का सारा वापिस ले लिया। उन्हें महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं है। इन्हें देने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन महाराष्ट्र के पास कोई अनुबंध नहीं था। महाराष्ट्र की मार्किटिंग की जो फैडरेशन है, उनके पास कोई साधन नहीं थे। आप इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? केवल प्याज की बात नहीं है, यह किसान की बात है। मुझे और किसी से मतलब नहीं है। मैं केवल एक बात जानता हूं कि किसान चाहे आपका हो या मेरा, इस कोने का हो या उस कोने का, उसका भला होना चाहिए लेकिन आप उसे तबाह करना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई पालिसी नहीं बना रहे हैं। गवर्नमैंट उस पर कब्जा किए बैठी है जबकि उस पर सरकार का एक पैसा नहीं लगा है। आप इसकी इनक्वायरी कर रहे हैं। आप किस बात की इनक्वायरी करना चाहते हैं? आप इनक्वायरी करने वाले कौन होते हैं? आपको उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उन्हें देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप डंडा लेकर किसान को तबाह कर रहे हैं। मैं आपके काम के बारे में सोच कर ज्यादा कुंठित हो जाता हूं। आज जितने भी काम हो रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। इनका विचार करने का ढंग देखिए।

While presenting the Budget for 1997-98, the then Finance Minister projected a revenue growth of 15 per cent which did never materialise. In 1997-98, the sharp deterioration in tax collection stemmed from a marked decline in revenue mobilisation from major taxes. Customs duty fell short of the Budget Estimates by 11,550 crores of rupees due to deceleration in imports, Union Excise Duty was lower by 2,383 crores of rupees than the Budget Estimates due to slow industrial growth. While presenting the Budgets for 1998-99 and for 1999-2000, the present Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, refused to draw any lesson from the past experiences. In 1998-99, Shri Sinha projected a revenue growth of 17 per cent and in 1999-2000, he has projected a growth of 20 per cent.

This is highly optimistic.

मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को सोच कर ऐसा करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं?

In two years, that is, 1997-98 and 1998-99, the shortfall has been more than Rs. 9,000 crore. It is to be kept in view that in 1997-98, more than 7,000 crores of rupees were received from VDIS, 1997. Shortfall in that year would have been much more but for this one one-time voluntary disclosure scheme which fetched more than 7,000 crores of rupees under Income-tax. There is no reason why such a sharp variation should take place if there was not a deliberate attempt to inflate the receipts and depress the expenditure to project an apparent comfortable picture of Government revenue.

Why do we want to camouflage certain things in a certain way?

आप सीधे-सीधे बताइए कि यह घपला है, इतनी कमी है और हम मिल कर इसे दूर करना चाहते हैं, तभी कोई बात बन सकती है। बजट एस्टिमेटस और रिवाइज्ड एस्टिमेटस के अनुसार काम करके बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं।

In the year 1995-96, though the Central Plan outlay declined by Rs. 4,255 crore from Rs. 78,849 crore at BE to Rs. 74,594 crore at RE stage, the shortfall in Budget support was only 164 crore of rupees. Budget support declined by Rs. 164 crore from Rs. 28,994 crore to Rs. 28,830 crore only.

It will appear from the table that in all these three years, the Central Plan expenditure has been less but non-Plan expenditure has been much more. Tardy implementation of Central Plan is manifested in all the three successive years. Therefore, there is no wonder that development has been sacrificed to meet the non-Plan expenditure.

आपने प्लान में पैसा कम कर दिया और एक्सपैंडिचर ज्यादा बढ़ा दिया।

Interest payment in 1998-99 as percentage of revenue receipts has increased to 49 per cent at RE from 46.3 per cent at BE stage. In 1997-98, interest payment as percentage of revenue receipts increased from 44.4 per cent at

BE stage to 47.4 per cent at RE stage.

In 1996-97, the interest payment as percentage on revenue receipts came down to 44.7 per cent. So, we have to always compare this and see how things are working in a downward trend. We have to take care of all these things.

The Budget also provides incentives for revitalising the economy which has become a pious wish. We do not want to live in pious wish. We want to progress so far as our general economy is concerned.

ये सारी बातें सरकार को देखनी चाहिये। अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि प्लैटिच्यूड और गलत धारणायों से देश को गुमराह न किया जाये। सरकार सामने आये और बताये कि उसने क्या किया और वह क्या करना चाहती है। कुछ कंक्रीट स्टैप्स लिये जायें क्योंकि जो बजट दिया गया है, उसमें सार्थकता कम है और धोखा ज्यादा है। वित्त मंत्री जी को हमारे सामने आना चाहिये और वे बतायें कि कृषि, को-आप्रेटिव और इन्वैस्टमेंट पर किस तरह से लोगों में कांफिडेंस बनेगा, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये, बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिये और बेघरों को घर देने के लिये सरकार क्या कर रही है। केवल नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलेगा। इस टैक्नीक को बंद करके सार्थकता पर हमारा साथ दें ताकि हम लोग सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकें।

सभापति जी, आंकड़ें यह है कि आज भी स्वतंत्रता के ५० साल बाद इस देश में १० प्रतिशत गांव के लोग गोबर के उपलों से खाना बनाते हैं। ५० साल के बाद आज भी इस देश के गांव में रहने वाले ७१ फीसदी लोग अपनी रोटी लकड़ी से बनाते हैं। गांव में रहने वाले केवल साढ़े तीन प्रतिशत लोग गैस का कनैक्शन लिये हुए हैं। गांव के ये साढ़े तीन प्रतिशत लोग गरीब नहीं है इसलिए २२०० करोड़ रुपये की सबसिडी जो गैस पर जाती है, वह गरीब के लिए नहीं है। वह गरीब के पास नहीं >आती । जो व्यक्ति सिगरेट पर पैसा खर्च करता है, जो सिनेमा के लिए १०० रुपये की टिकट लेता है, जो किसी रेस्टोरैंट में ५०० रुपये या हजार रुपये का बिल चुकाता है, यह २२०० करोड़ रुपये की सबसिडी उसको जाती है। इस बात को सोचें और विचार करें।

७००० करोड़ रुपये की सबसिडी मिट्टी के तेल पर हम दे रहे हैं, उसका उपयोग कौन करता है? गांव के अंदर मिट्टी के तेल लेने वाले केवल तीन प्रतिशत हैं मिट्टी का तेल शहरों में बिकता नहीं है, वह ब्लैक में जाता है। इस ७००० हजार करोड़ रुपये की सबसिडी का फायदा गांव के गरीब को, आम आदमी को नहीं होता है, यह ब्लैक में जाता है। डीजल में पेट्रोल की मिलावट होती है। दूसरे शब्दों के अंदर ७००० हजार करोड़ रुपये की सबसिडी हम पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के लिए देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है। ... (व्यवधान) मैंने जो बात कही है।

... (व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सवाल पर एक सहमति बननी चाहिए कि एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये की जो सबसिडी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दी जाये। मैं कहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो ३२ करोड़ लोग हैं, उनको दुगुनी सबसिडी दे दी जाये। लेकिन यह सबिसिडी अमीरों को क्यों जा रही है? आखिर देश को हमें आगे बढ़ाना है इसलिए मैंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने जो इशारा किया है, उस पर सहमति बने और इन सारी सबसिडीज के बारे में हम f वचार करें।

मैं पांचवें पे कमीशन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उससे पूरे देश की राज्य सरकारों पर लगभग ९० हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। केन्द्र की सरकार पर १०-१२ हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। इतना भारी बोझ पड़ा कि उस समय की सरकार ने राज्यों से पूछा ही नहीं, राज्यों से सलाह नहीं की और बिना राज्यों से पूछे निर्णय कर दिया जिसका प्रभाव वहां पर पड़ा। पे कमीशन ने और बातें कही थीं कि साढ़े तीन लाख पद न भरे जायें, दस साल में सरकार का साइज ३० प्रतिशत कम किया जाये और ४० वर्किंग डे बढ़ाये जायें। उसके बारे में नहीं सोचा गया।

मैं बुनियादी बात कहना चाहता हूं कि पे कमीशन जब बनता है तब उसका एप्रोच क्या होता है? लोग बैठते हैं और कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी की जरूरतें बढ़ गईं, महंगाई बढ़ गई, उसका स्टेटस बढ़ गया इसलिए उसको पैसा दो और वह पैसा दे दिया जाता है। मेरे विचार से यह एप्रोच गलत है। एप्रोच यह होना चाहिए कि देश के पास कुल कितने साधन हैं? ३२ करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं, उनको भी देना है। जो आर्गनाईज्ड सैक्टर हैं, वे शोर मचाकर सब कुछ ले जाते हैं लेकिन जो गरीब शोर नहीं मचा सकते, सड़क पर नही आ सकते, उसके बारे में अगर यह सदन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एप्रोच इन सवालों पर बनना चाहिए।

मैं सार्वजनिक उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इससे दो लाख चार हजार करोड़ रुपये लगे हैं और उनमें ४१ हजार करोड़ रुपये का घाटा है।

उसमें १० हजार करोड़ रुपये डिसइन्वैस्टमैंट करने का निर्णय माननीय वित्त मंत्री जी का सराहनीय कदम है। मैं चाहूंगा कि इससे अधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का धन है जो वहां पर लगा है और घाटा दे रहा है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिछले वर्ष ५ हजार करोड़ रुपये का लक्षय तय किया गया था लेकिन ८ हजार करोड़ रुपये की डिसइन्वैस्टमैंट हुई हालांकि समय केवल नौ महीने का था। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रकार के उद्योगों को, जिनके बारे में कमीशन की ओर से सलाह आई है, हमें थोड़े शेयर्स रिलीज करने चाहिए, मैनेजमैंट ऐफीशैंट प्राईवेट हाथों में देनी चाहिए, जब शेयर्स की कीमत बढ़े तब बाकी शेयर्स रिलीज करने चाहिए। इससे उन सिक यूनिटस में ऐफीशैंसी आएगी, वे ठीक होंगी और सरकार को अधिक पैसा मिलेगा।

सरकारी खर्चों को कम करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिशा में शुरुआत की, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सरकार ने सरकारी खर्चे कम करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, यह सराहनीय बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह इच्छा केवल इच्छा न रहकर

इच्छा शक्ति बननी चाहिए। उधर से बिल्कुल ठीक कहा गया कि देश की हालत काफी खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पचास साल के बाद हमारे देश की क्या हालत है। जब इस पर विचार किया जाता है तो कई बार मन बड़ा परेशान होता है। पिछले सात सालों के अंदर लगातार यह स्थिति आ रही है कि टोटल डैट सर्विसिंग को पूरा करने के लिए भी हमारी आमदनी नहीं है। इस साल की हालत यह है कि हमारी शुद्ध रिवैन्यू रिसीट १ लाख ८२ हजार करोड़ रुपये है, लेकिन पिछले उधारों की वापसी १ लाख ७ हजार करोड़ रुपये, उधारों का ब्याज ८८ हजार करोड़ रुपये, टोटल डैट सर्विसिंग १ लाख ९५ हजार करोड़ रुपये और आमदनी १ लाख ८२ हजार करोड़ रुपये है। हम पचास सालों में कहां पहुंच गए। जो इनकम आ रही है, उससे डैट सर्विसिंग नहीं हो पाएगी और पिछले सात साल से यह हालत चल रही है। आज देश पर ८ लाख ५० हजार करोड़ रुपये उधार हो गया है। यह पचास साल की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि प्लान ऐक्सपैंडीचर, नॉन प्लान ऐक्सपैंडीचर, तनख्वाह देने का काम आदि उधार लेकर किए जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। इसलिए परस्पर सहमति से कुछ कड़वे फैसले लेने चाहिए।

सरकारी खर्चे कम करने के बारे में हमारी सरकार चिंतित है, प्रधानमंत्री जी नें अपना संकल्प प्रकट किया है, वित्त मंत्री जी ने कहा है। यह क्यों जरूरी है? आंकड़े देखें तो बड़ी परेशानी होती है। १६ साल में सरकार का खर्चा कितना बढ़ा, मेरे पास उसके आंकड़े हैं। १९८०-८१ में भारत सरकार का नॉन डैवलपमैंट ऐक्सपैंडीचर ९८६७ करोड़ रुपये था और १६ साल के बाद १९९६ में यह खर्चा १ लाख १४ हजार करोड़ रुपये हो गया। प्रदेशों का खर्चा १९८० में ४२०० करोड़ रुपये था जो १९९६ में ६३ हजार करोड़ रुपये हो गया। देश का कुल नॉन डैवलपमैंट खर्चा १९८० में ३७ हजार करोड़ रुपये था जो १६ साल बाद १९९६ में ३ लाख ४३ हजार करोड़ रुपये हो गया। बेतहाशा, बिना सोचो-समझे यह वृद्धि, मुझे लगता है कि जब देश गुलाम था, जो शहनशाह थे, मुगलियत सल्तनत के नवाब थे, वे भी इतनी बेरहमी से देश के धन को इस ढंग से बेतहाशा खर्चे बढ़ाकर नहीं करते थे जिस ढंग से पिछले दिनों हुआ है।

अगर हम अपनी इन्कम से तनख्वाह नहीं दे सकते, तो जैसा मैंने कहा, इस पर गहराई से देखें। अगर किसी घर की आय १०० रुपये हो और उधारों की वापसी १५० रुपये करनी हो तो वह घर उजड़ जायेगा। ५० साल के बाद इस देश को भी यहां पहुंचा दिया गया है। इसलिए सरकारी खर्चे घटाने की दिशा में जो प्रयत्न शुरू किया है, मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह काफी नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें बहुत स्कोप है।

हिमाचल प्रदेश में भी संकट आया था, जब मैं मुख्य मंत्री था। हमने एक साल में ५४ करोड़ रुपये की बचत की थी। कुछ निर्णय कर लिये, क्लास वन, क्लास टू के जितने पद खाली थे, हमने कोई नहीं भरा। शानो-शौकत, ताम-झाम, तड़क-भड़क कम की, टेलीफोन काटे, टेलीफोनों पर सीलिंग लगाई, सरकारी गाड़ियों पर सीलिंग लगाई और एक साल में ५४ करोड़ रुपये की बचत हिमाचल प्रदेश ने की थी। मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में एक सहमति बनायें, वित्त मंत्री जी को शक्ति दें, बल दें। वित्त मंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न करें। मैं यह समझता हूं कि यदि प्रयत्न किया जाये तो नॉन डवलपमेंटल खर्चे को कम करने के लिए बहुत स्कोप है। हम एक गरीब देश की सरकार हैं, जिस देस में ३२ करोड़ लोग रोज रात को भूखे पेट सोते हैं, हम उस देश की सरकार हैं, इसलिए फिजूलखर्ची कम की जाये, बन्द की जाये। ताम-झाम, तड़क-भड़क, जश्न, इस किस्म की सारी बातें पूरी सरकार के अन्दर ऊपर से लेकर नीचे तक कम करके एक सादगी की संस्कृति स्थापित करने की कोशिश की जाये। जो क्लास वन, क्लास टू के खाली पद पड़े हैं, कोई बहुत आवश्यकता हो, तभी भरे जायें, नहीं तो उन सारे पदों को न भरा जाये। विदेशी दौरों पर अंकुश लगाया जाये, गाड़ियों के काफिलों के दौड़ने पर अंकुश हो। टेलीफोनों पर कितना खर्च होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में जब हमने टेलीफोनों को रोकने की कोशिश की तो ऐसे अधिकारी, जिनको कभी पांच बजे के बाद टेलीफोन करने की जरूरत नहीं थी, उनके बिल २२,००० रुपये, ३२,००० रुपये के हमने देखे। हमने सब के टेलीफोन बन्द कर दिये, उन पर अंकुश लगा दिया।

एक-एक बूंद बचायी जाये तो समुद्र भरता है, एक-एक बूंद लुटाई जाये तो समुद्र खाली हो जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडीचर के अन्दर शानो-शौकत बन्द की जाये, सादगी लाई जाये, खाली पदों को न भरने का निर्णय आप सब के सहयोग से किया जाये, विदेशी दौरों में कमी की जाये।

आजकल हमारे पास कलैण्डर डायरियां आ रही हैं, मैं आजकल जिस घर में रह रहा हूं, उसके चार कमरे हैं और २०-२५ कलैण्डर आ गये हैं। इम्पोर्टिड आर्ट पेपर पर मैंने कुछ विभागों की रिपोर्ट देखी, जो हमें आई थीं। उन्हें कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, वे अलमारी में रखी रहेंगी, फिर रद्दी में जाएंगी। इम्पोर्टिड आर्ट पेपर की एक-एक रिपोर्ट ५०० रुपये, १,००० रुपये से कम नहीं पड़ेगी। हम गरीब मुल्क हैं, सादे कागज पर रिपोर्ट क्यों नहीं छपती? सरकार का केवल एक विभाग कलैण्डर क्यों नहीं छापता? ३२ करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक सहमति बनाकर सादगी का वातावरण पूरे देश में लाने की कोशिश की जाये। मेरा अनुभव है, मैं विश्वास से यह कहता हूं कि यदि यह सादगी का वातावरण लाने की कोशिश की जाये तो कम से कम १० परसेंट नॉन प्लान, नॉन डवलपमेंटल खर्चे में बचत भारत सरकार कर सकती है और वह २०,००० करोड़ रुपये की बचत होगी। कम से कम १० परसेंट की बचत प्रदेश की सरकारें कर सकती हैं, वह २५,००० करोड़ रुपये की बचत होगी। लेकिन ये सारी बातें तभी हो सकती हैं, जब सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करेंगे।

मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं, आज यहां सुबह-सुबह चर्चा हुई, कल दिल्ली में यमुना के किनारे कुछ झोंपड़ियां जल गईं। इस समय उन घरों में मातम की काली छाया है। हमने यहां कुछ बातें कीं, कुछ शोर मचाया, सहानुभूति प्रकट की। कमीशन बैठेगा, चर्चा होगी, चर्चा बन्द हो जायेगी, फिर कहीं आग लगेगी। आखिर सोचने का विषय तो यह है कि ५० साल की आजादी के बाद यहां दिल्ली में हम सब की नाक के नीचे लाखों लोग झोंपड़ियों में क्यों रहते हैं? आखिर हम करते क्या रहे? आजादी के सूर्य की किरण गरीब की झोंपड़ी में नहीं पहुंची है।

19.00 hrs.

इसलिए कुछ कठोर निर्णय करना जरूरी है। मैं समझता हूं आवश्यकता इस बात की है कि देश में जो ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह ५० साल की नीतियों का परिणाम है। आज देश में आर्थिक रूप से विशेष परिस्थिति है, यह सोचकर सब लोग मिलकर एक सहमति बनाने की कोशिश करें और सहमति बनाकर कुछ बुनियादी, क्रांतिकारी परिवर्तन आर्थिक नीतियों में लाएं। इस दिशा में आज प्रधान मंत्री जी ने जो जिक्र किया, मैं समझता हूं वह बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र है कि सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की है। इसको रोकने की जरूरत है। यदि देश ने समय पर पग उठाए होते और ७० करोड़ पर जनसंख्या रोक दी होती तो आज देश की यह हालत नहीं होती। आज हमारे देश में ५० हजार लोग प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हर महीने १५ लाख लोगों की वृद्धि होती है और वर्ष में एक करोड़ ७६ लाख लोग बढ़ जाते हैं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है बड़े साधन, बड़ा राष्ट्र, इस बारे में सरकार के द्वारा जो नीति

बनाई जा रही है, उस पर ईमानदारी से सख्ती से अमल हो। कोई भी तरीका जो देश के हित में हो सकता है, उसे अपनाना चाहिए, नहीं तो आने वाले कल को अंधकार में धकेलने की कोशिश करेंगे।

हमें सरकारी खर्चों को रोकना चाहिए, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिए। देश के साधन अन्य ढंग से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं, जो सीधे गरीब तक नहीं पहुंच पाते। मेरा यह अनुभव है कि जो सबसे नीचे बैठा हुआ गरीब है, उस तक कम चीजें पहुंच पाती हैं। इस देश में ३२ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई नई योजना, जो केवल उन तक, जो सबसे नीचे बैठे हैं, के लिए बनाएं। पहले भी ऐसा प्रयोग हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हमने अंत्योदय योजना शुरू की थी। एक लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई थी जो सबसे गरीब हैं। हमने देखा कि इससे १० प्रतिशत परिवार एक साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए थे। हमारे देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको लागू करने पर भी हमने देखा है कि नीचे तक कम ही योजनाएं पहुंचती हैं। जो ३२ करोड़ लोग भूखे पेट सोने वाले हैं, जिन्हें आजादी का हिस्सा बिल्कुल नहीं मिला, उनको आइडेंटिफाई करके केवल उनके लिए कोई योजना अंत्योदय केरूप में शुरू करें, ताकि उनको सीधे लाभ हो।

आज की परिस्थिति में जो जर्जर आर्थिक स्थिति हमें विरासत में मिली है, उस पर इतना बढ़िया बजट आजादी के बाद पहली बार पेश किया गया है। यह ग्रामीण प्रधान बजट है। इसलिए मैंने जैसा पहले कहा कि वित्त मंत्री जी को और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इन परिस्थितियों में बड़ा अच्छा बजट बनाया है। जिसका परिणाम देश की आर्थिक स्थिति पर अच्छा होगा। लेकिन देश की हालत को ठीक करने के लिए, मिलकर कदम उठाने होंगे, कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, वरना झुग्गी-झोंपड़ियां इसी तरह से जलती रहेंगी, हम भाषण करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए आर्थिक परिस्थितियों में हम अच्छा निर्णय करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

>>

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं इस ऊं>बढ़िया बजट' का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं

... (व्यवधान)

क्योंकि आपने इसे बढ़िया कहा है इसलिए मैंने आपकी बात कोटेशन में रखी है।

I oppose the General Budget presented by the hon. Finance Minister on 27th February, 1999. My opposition to it rests primarily on five grounds.

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मैं इस ठबढ़िया बजट' का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं

... (व्यवधान)

क्योंकि आपने इसे बढ़िया कहा है इसलिए मैंने आपकी बात कोटेशन में रखी है।

I oppose the General Budget presented by the hon. Finance Minister on 27th February, 1999. My opposition to it rests primarily on five grounds.

What are they? The General Budget, as presented by the Finance Minister, lacks in direction. It is a directionless Budget. I may call it that it is a futile exercise with fudged figures. With a sleight of hands, he wanted to present some magic. But the people of India and also those who think about India, will never be convinced. Rather, they will question his credibility about his figures and all this. I will come to that later on.

This Budget fails miserably -- I repeat `miserably' -- to address...

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Are your repeating the same thing today?

SHRI RUPCHAND PAL : No. I am responding to the figures presented by him and how miserably he has failed. This is the Economic Survey of 1998-99, Let us have a look at the key indicators. I will read only two or three lines. I think, the Members must have gone through it.

I come to the Industrial production. During 1995-96, the industrial production was at 12.8 per cent . During 1996-97, it was at 5.6 per cent. During 1997-98, it was was 6.6 per cent. And, this year during the time of

coming to the press it was at 3.5 per cent. Even the Finance Minister has agreed that the industrial Sector has a recessionary condition has been prevailing in the country.

Earlier, when we were discussing about the East Asian crisis, this Govt. have been talking eloquently that `we are insulated. We do not have any short-term debt. Moreover, we have not gone for capital convertibility.' They have become wise. Those who have been advocating for it, took a `U' turn and have been just taking pride for what they wanted to take. But could not. About the ailing economy, the recession-hit industrial sector and the negative growth in the export, I am not quoting the figures. They are there in the key indicators.

Also, I oppose the General Budget as it has failed to address food production, rising unemployment, unbearable price burden on the common man, the growing poverty, rising gap between the millions and millions of poor people of this country and the handful of rich, the Budget has not addressed all the serious issues. Also I oppose this Budget, because on the year of the `Swarana Jayanti' of our Independence, there is a concerted, deliberate and planned move to mortgage the economic sovereignty of this country. They want to erode our base of self-reliance. They have deliberately decided to weaken our public undertakings through outright priviatisation and through unethical manipulations by equity swaps, that is, cross-holdings amongst three profitable public undertakings, ONGC, IOL and GAIL. And, this Government has earned to the tune of Rs. 3,500 crore behind their back in a very unscrupulous manner -- I repeat the word `unscrupulous'.

1909 hrs (Shri K. Yerrannaidu in the Chair)

Now, we find that some very important officials of the Government are saying that `if the prices of shares of these public sector undertakings have gone down in the market, they are themselves responsible.' Why did they not convince the people about the reasons for which they had undertaken such a measure and the responsibility lies on them-the management of these Public Sector Undertakings. But the decision was imposed on them. I oppose this because this has been done to erode the base of our public undertakings, our goal of the self-reliance.

Sir, this Government has already pushed this country into a debt trap. What is a debt trap? We call it a debt trap when your liability for debt service is more than what you are borrowing. That is, you require more than what you borrow that for debt servicing.

I would like to directly ask the hon. Finance Minister. He said : -

"Receipts through borrowing etc., will be Rs.79,955 crore."

The new accounting has come and I shall come to that later. There is something new in the Budget. There is new accounting procedure and there are new series. In the new accounting procedure, the small savings loan has been excluded as a result of which the figures have become very comforable for the Government. It lacks credibility. The Finance Minister, by the trick his hand, by manipulation, by new accounting procedures, by change of series and by new denominators tried to present a magical picture of the economy. It is a jugglery.

They say that they will borrow Rs.57,461 crore which is Rs.64,909 crore less than current year. But what is our experience for the last several years since the so called economic reforms were undertaken . You did not initiate it. You are very obediently following anti-India measures every year and the borrowing is rising. How will it now suddenly come down by 11 per cent? (Interruptions) I will come to nobel prize part later on.

This is not the only sign. There will be rise of 20 per cent revenue. We know what has happened to our reaching the target last year. Current year performance is miserably less than the target. Suddenly he imagined that it will come up by 20 per cent. I will come to that later on. Leave it at that right now. I shall deal with it later on.

They are directly pushing the country into debt trap. There are certain new things in the Budget. What are they? First, let me take those new things. One is, they have changed the base in the series.

Secondly, they have changed the accounting procedure.

Thirdly, they have changed the names of certain projects which were in the name of Pandit Nehru or, for that matter, Shrimati Indira Gandhi. They have done away with it. They have incorporated the name of one of their great leaders, Deen Dayal Upadhyay. What is more, earlier the Budget speeches were concluded with Ghalib, Ikbal, Rabindranath Tagore and now the Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. Shri Atal Bihari Vajpayee, Ikbal, Ghalib and Tagore are at the same level. That is a new feature of the Budget!

SHRI VAIKO (SIVAKASI): You could not understand the poetic touch of Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI RUPCHAND PAL : I shall try to understand after a few months when the people will give you the right sort of thrashing as they have given you during the last Assembly elections.

Now, a new scheme has been proposed under the name: great name has come up, `National Human Development Initiative', which bears the shadow of the Nobel laureate, Prof. Amartya Sen. We know the response of the RSS and such other people when he was given the Nobel Prize. We know how they reacted. We also know how the Government reacted but I am not mentioning it right now because they had ultimately changed their position. So, I am not repeating that. How was the response? What was the reaction? What happened at the research centre at Shimla? I am not going into all these details but the shadow of Prof. Amartya Sen is there. The name `National Human Development Initiative' has been given and it can be found in Part I of the Budget speech of the hon. Minister of Finance.

As you know, Prof. Amartya Sen and some other people - there is also the great Pakistani economist, Mahboob-ul-Haq - have been influencing the United Nations to just reorient its outlook and decisions, particularly with regard to the developing countries and they have successfully done it. As a result of that, ultimately, the World Bank and many other such global agencies had to take different decisions on the role of the State. Earlier, they have been speaking about minimal Governments but ultimately the World Bank decided that the State has a role to play with regard to areas where the private sector will never come, where there is hardly any profit in areas like education, healthcare and so on.

When Prof. Amartya Sen, as it came out in the Press, met the hon. Minister of Finance and also the hon. Prime Minister - I think it was a meeting at the `Taj Mansingh' - he had made certain suggestions that if India has to make any progress, the areas which should be taken care of seriously are food security, health care, elementary education and such other things. Now, after this meeting, they have come up with the National Human Development Initiative. For the first time in free India, they are the only people to have thought of such things.

उन्होंने कहा कि क्रांतिकीरी कदम उठाये जाएं, पंचायतों को इनवाल्व किया जाए।

Let us take a look at the figures. I am coming to the figures one by one. On food security, there was a conference at Delhi very recently attended by very eminent people. Dr. Vandana Siva and such others attended the conference where the conclusion was that the per capita availability of food in India is going down and down. It is at such a point of time that they are thinking of this National Human Development Initiative. But how was the initiative taken? Just before the Budget, the prices of wheat, rice and sugar have been increased. They have later reduced the prices only for the people below the poverty line. There is a marking, a lakhsman rekha called `below the poverty line'. This Government does not know the lower middle class people who have to depend on the public distribution system absolutely. Technically, they may not be below the poverty line but they have taken the food of the lower middle class working people away.

After taking away food from these people by increasing the prices of wheat, rice, etc., they very bravely say, in the Budget that they are undertaking a National Human Development Initiative.

Let us come to elementary education now. There is a study made by the Government itself. Shri Amartya Sen was very specific on this issue; he says that if there is a will, there is no dearth of money; money will never stand in the way. An eminent economist Tapas Majumdar has come out with a study saying that it is possible, if the Government has mind alone. The Oxford University Press has come out with a public report on basic education. I know that there is a calculation that an approximate amount of about rupees one lakh and thirteen crore would

be required over a period of ten years to make India to provide elementary education to all children between 5 and 14 years of age Although I do not think the figure would be correct or the study would be correct because later on there had been several other studies which differed on the amount required.

I am coming to the figures on how in this year's Budget they had proposed to undertake the National Human Development Initiative. At least, they have learnt that this term should be used because for so many years, there were several indicators like that of the World Bank, the UNDP, etc. I am coming to the figures on elementary education now. Operation Black Board and all other things taken together, in 1998-99, it was Rs.304 crore; the revised figures during 1998-99 is the same. During 1999-2000, it is Rs.400 crore. What a graceful gesture they had shown for a country with half of the population living below poverty line and with more than one-third of the population being illiterate, particularly the womenfolk who have hardly any opportunity to have education! This is a revolutionary step that they have taken! When the Government has calculated that an amount of rupees one lakh and thirteen crore or at least an amount of rupees ten thousand crore is required for each year, for ten years, for providing elementary education to all children. They have now provided Rs.96 crore in addition. What a revolutionary gesture they had shown!

In the case of total elementary education - the district primary education and all other things taken together - during 1998-99, it was Rs.2780.03 crore and the revised figure was Rs.2743 crore, that is, it has come down. Now, they have said that it is Rs.3034.95 crore, which is the total figure. Am I correct? ... (Interruptions) It is a spectacular rise! Their own Government has calculated that it requires an amount of rupees one lakh thirteen crore for elementary education. It is like paying a lip service to the views of Shri Amartya Sen. It is a caricature of the National Human Development Initiative that is being undertaken in other countries. That is why, in the human development index we are in 139th position. Even Pakistan is above us; even some other smaller countries of the world are above us. Are we not ashamed? We are a big country with 98 crores of population, with so much resources, with so much talent and have so many professionals and scientists; we had Pokhran tests also and after Pokhran we find that we cannot just go one position up and reach the position of 138th.

Pakistan is above us. We cannot just go one position up, that is from 139 to 138. Many more epithets are being used; within a few years we shall be this or we shall be that. You should first bring the position up from 139 to at least 130. Is there anything in the Budget by which the Minister can assure the House on this? I would like to know from the Finance Minister, is there anything in the Budget by which he can bring India from 139th to 130th position. Can he assure the House? The Minister lacks credibility. He has fudged figures. He has befooled the people by giving new names only. This is not only true about the elementary education but the same is true about the health care also.

There have been studies conducted by the Government. The Government is a continuing body. Studies are being conducted for universal immunization, pulse polio, resurgence of malaria, leprosy eradication programme and so on. It was once said that there was no leprosy in India. Today, in many parts of India, we find resurgence of Leprosy. How much has the Minister provided for that in the Budget? I can go on reading the deceiving figures. There is nothing substantial by which the Government can say that it has taken any initiative at all to address to the situations like, debt, industrial recession, food, security, health care or education. In such a situation, what is it that the Government has done? I would not take much time of the House as other Members have also to speak.

The Government has imposed more burden on the common people. Our revenue collection will be 20 per cent more. We have restructured our indirect tax system. What a great thing the Government has done! From 11 rates the Government has brought it down to three rates. I am not going into everything. Allopathic medicine will be costlier now. The Swadeshi people will be happier to know that beer, wine and whisky will be cheaper. What an excellent restructuring of the indirect taxes! I can go on reading; X-Ray film, will be costlier. Although there is resurgence tuberculosis .The other day the Health Minister was saying this -But the X-Ray films would be costlier. The Government say that the things which affluent class of people use, many more things related to the life of upper strata of people, will be cheaper while machine parts, batteries, will be costlier... (Interruptions) They know how to manage it. In the name of restructuring, the Government has proposed such measures that the whole burden will fall on the common people.

I now come to the Direct Taxes.

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : जिन चीजों के दाम कम हो रहे हैं, वे नहीं बताए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : व्हिस्की और बीयर के बारे में बताया।

I can give you any number of instances. But I have so many points to make. How will this Government just meet the situation? Where will the money come from to cover the deficit? Rupees ten thousand crore will come from the disinvestment of public sector undertakings. Now the situation is such that even when they say that they want to sell, people say that they are not interested in buying. This is the experience of all these years. Be it the case of Rail Bond or any other thing. So, they want to earn Rs.10,000 crore from disinvestment. But I do not think this will happen.

Now, I come to capital market. They have proposed a Gold Deposit Scheme. Oh, what a revolutionary step! Earlier a Gold Bond Scheme was there. Such schemes are coming from the days of late Morarji Desai. I am here since a quite long time. So many times such schemes have come. Every year so many amnesty schemes come with new names. Now they say that so much imported gold is coming. Now they will reward the wrong doers who have brought the gold and who have stashed the money. Now they will bring back the money by rewarding the wrong-doers. A part of the hoarded gold has come from smuggling, some of which represent tax evaded blackmoney.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Specific time has been allotted for each party.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I have hardly started. I will speak up to 8 o'clock today.

Sir, on blackmoney, over the years due to inflation and most importantly due to the depreciation in the exchange value of the rupee the price of gold had been rising by 15 per cent per annum. This is not my study. This study had been made by your own people. People say that there is better return by keeping them in the form of gold. What is the response to this? As per Dr. Manmohan Singh's a Gold Deposit Scheme without some sort of amnesty will never be successful. So, I do not know whether this is going to be another amnesty because there is not a word about blackmoney. This is a reward announced for the hoarders of blackmoney.

Immediately, after this Budget was presented people from capital market were very happy as it was rising. Of course, he was not losing his sleep. I have no hesitation in saying that the balloon is going to burst any moment. It is because the rise is restricted to 5-6 areas, namely, information technology, two-three banks, Hindustan Lever, SBI and certain other things. This is due to the operations by the foreign financial investors. I do not know what the great operates of the Security Scam are doing. He has been doing something with sterlite Videocon, BPL and all those companies. There was an apprehension expressed by very important persons that it was reminding us of the days of Dr. Manmohan Singh. When his attention was drawn to the situation, he said that he could not lose his sleep over it. I do not know whether the Finance Minister is really thinking what is happening in the capital market, for, it has no relation with the fundamentals. There is industrial slow down and there are recessionary conditions prevailing in the country. There is no growth in exports. But suddenly one morning, immediately after the Budget was presented, there was resurgence in the capital market. After that, as the indications were given by the Finance Minister, the Reserve Bank of India cut the interest rate. People whose money were in the postal savings, were bound to go to mutual fund.

The first step was taken by reducing the interest of the postal savings and after that, encouragement was given to mutual funds. In our country, we know the most unscrupulous operations made by some of the mutual funds. I am not naming them. But now it is a virtual loot of the middle class people, the salaried people and the retired people who had kept their money, after retirement, in postal savings and such other areas. They will be deprived of their earnings at the end of the month.

The Budget will cause price rise. The food articles and other essential articles needed by the common people will be hoarded.

MR. CHAIRMAN: The remaining points may be covered by other Members of your party. Please conclude now.

SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding. Sir, for your interest, I shall be telling you some points. This forms the open agenda. I had not come to the hidden agenda till now. It would be interesting for you because you are supporting the Government.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): You should not say like that because he is in the Chair now.

SHRI RUPCHAND PAL : All right. I am sorry, Sir. Your party is supporting the Government.

MR. CHAIRMAN: There are three more Members to speak from your party.

SHRI RUPCHAND PAL :I shall come to that later but this is very interesting for you. We shall take it up again when we discuss the Finance Bill. But still, I shall be failing in my duty if I do not mention it. This has never happened in free India. I would refer to page 11 of the Memorandum explaining the provisions of the Finance Bill. It says:

"Deduction for donations made to funds or institutions for charitable purposes: Many institutions which are carrying out charitable work are often inspired by the tenets of religion. In order to allow them to show respect to this aspect without depriving them of the benefit of this section, it is proposed to amend the provisions of Section 80G so as to provide that in case such institution or fund spend not more than five per cent of its income during the relevant previous year for religious purpose, the benefit of this section will not be denied to them."

Many institutions which are carrying out charitable work are often inspired by the tenets of religion. They spend on shells of small bricks, flowers, lotus and all these things and collect a huge amount.

Sir, in the Preamble of our Constitution, it is written that we are a secular democracy. This has never happened in free India that religious institutions have been encouraged to collect money. This is the situation where we are placed now.

Industry is totally in the grip of recession. Food production has come down. Unemployment is increasing everyday. Everyday, we hear, in this part of the country or that part of the country, that some public sector undertakings have been closed.

MR. CHAIRMAN: You have consumed thirty minutes. You are a senior Member and have participated in many debates. Kindly conclude now.

SHRI RUPCHAND PAL : I would conclude in two minutes.

Profitable public sector undertakings are being ruined through outright sale and things like that. Do they care for unscrupulous private companies? I will name only one or two companies. There is a company called Dunlop India Limited. I had been to the Prime Minister, Industry Minister and Finance Minister. They know that a Dubai-based NRI who now controls that Company has siphoned off the Company's funds and for the last seven years, they are looting money. The financial institutions do have 33 per cent of the share. On 12th January, 1998, the nominee of the financial institution, LIC, deliberately collaborated with these unscrupulous management to declare the Dunlop India Limited sick.

More than 4,500 workers are working in it. More than one lakh people are dependent on it. People are starving. Even last Friday, one employee committed suicide. This Government has no responsibility. It is a good company. It can produce different types of tyres. The tyres have got a good market abroad. It is producing road tyres, conveyor belts and steel cords. It is such a good and reputed company. Whereas those people are ruining it and looting the money of the financial institutions. We are silent spectators. It is true about many other companies also.

This Government is practising discrimination. I am giving one example and with that I conclude. The State Bank of India, Calcutta, has in its Foreign Division, the Inter-Bank activities like transfers. Suddenly, they decided that it should be shifted to Mumbai. We approached the Finance Minister. We approached the Prime Minister. A

delegation of Members of Parliament met the Prime Minister on 17th December. The Prime Minister spoke to the hon. Finance Minister over telephone and he assured us that the shifting would never take place. But still we find that a major part of the Inter-Bank working in the foreign Division of SBI, Calcutta is being shifted in such a way that suggests attitude of discrimination.

There is discrimination against a State where an opposition party is ruling. They are depriving of the finances of the State. Small Savings was a major area where the State has been doing well. The States will suffer. A State like West Bengal mobilised the highest amount through Small Savings...(Interruptions) I am concluding now. Let me thank him...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There is no question of concluding. Every time, you are telling the same thing.

SHRI RUPCHAND PAL : While concluding, I would like to say that I oppose the Budget because it is anti-people and anti-poor. I conclude...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Bashist Narain Singh to speak.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no need of any recommendation. I am following the rule.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Bashist Narain Singh.

(Interruptions)*

---

* Not Recorded.

>

श्री वशिष्ट नारायण सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मैं भारत के वित्त मंत्री ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से श्री यशवंत सिन्हा जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जबकि भारत में वित्तीय संकट और विश्व व्यापार में मंदी चल रही हो, जबकि भारत में बेरोजगारों की संख्या आजादी के इतने वर्षों के बाद बढ़ती गई हो, जबकि भारत में आज यह भी सवाल उठ रहा हो कि गावों में लाखों-लाख की संख्या में लोगों के लिए अभी आवास का प्रबंध करना हो, जब देश के सामने ऐसा संकट भी हो कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी जमीन की व्यवस्था आज तक ठीक से नहीं हो पाई हो, पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाया हो, जब मजदूरों की संख्या अधिक बढ़ती गई हो, जब कि भारी संख्या में लोन लेकर पचाने वालों की संख्या में भी कमी न आई हो और हजारों करोड़ रूपया लोन लेकर उसका दुरुपयोग करने का काम किया हो, जब ऐसी स्थिति वर्तमान हो तथा साथ ही साथ भारत के वित्त मंत्री के सामने संसार का आर्थिक संकट और समृद्ध देशों की भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदियां भी हों, ऐसे समय में वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने का जब मौका आता हो, तब उनके सामने कितनी समस्याएं और किस ढंग की दिक्कत होगी इसे आसानी से समझा जा सकता है।

सभापति महोदय, जब यह वित्त बजट प्रस्तुत हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में आर्थिक पाबंदियों की छाया भी बजट के साथ-साथ चलती आई है।

सभापति महोदय, जब भारत का यह वित्त बजट पेश हुआ, उसके पहले देश ने परमाणु परीक्षण करने का काम भी किया। उसके अलावा भी और कई ऐसी बातें हुईं हैं आर्थिक पाबंदियां लगाने के बाद और मल्टी नैशनल का विश्वव्यापी स्वरूप होने के बाद, भारत का यह बजट पेश हुआ। इसलिए वित्त मंत्री के समक्ष उ पस्थित कठिनाइयों को आसानी से समझा जा सकता है।

सभापति जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी इस देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो करोड़ों अरबों रुपए के बैंक के लोन पचाए बैठे हैं। मैं आंकड़े भी नहीं देना चाहता हूं कि अभी इस देश के ऊपर कितना ऋण है और देश के राजस्व से कितनी प्राप्ति हुई है। हालांकि इन सभी बातों पर विस्तार से कहने की आवश्यकता थी, लेकिन बोलने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है इसलिए मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस वर्ष का प्रथम बजट है जो ठसिंहासनी भाषा' और ठसतही उपचार' से मुक्त होकर प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा बजट है जिसने भारत की समस्याओं को सही परिप्रेक्षय में पहचानने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं सिंहासनी भाषा से मुक्त और सतही उपचार वाला बजट जो कह रहा हूं, ऐसा कहने के मेरे अर्थ स्पष्ट हैं। सतही उपचार जब मैं कह रहा हूं, तो ऐसा कहने के पीछे इस देश की आजादी के इतने वर्षों की कहानियां छिपी हैं। इसलिए सतही उपचार का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने सभापति महोदय कुछ चीजों को छूने का काम किया है। चूंकि भारत की समस्या और विश्व के समृद्ध देशों की समस्या एक नहीं है। आज अमरीका और यूरोपीय देशों के सामने जो सवाल हैं, वे सवाल भारत के लोगों के सामने नहीं हैं। समृद्ध देशों के लोगों के सामने आज यह सवाल है कि वे बेहतर जीवन कैसे जिएं, लेकिन भारत के लोगों के सामने सवाल यह है कि जिन्दकी को कैसे जिया जाए। इसलिए भारत का जो बजट होगा उसमें इस चीज को निश्चितरूप से ध्यान में रखा जाएगा और इस बजट में इसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।

महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं इसलिए मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जितना अर्थशास्त्र जानता हूं उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भारत में पूंजी कम है लोग ज्यादा हैं, जमीन कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं यहां वित्तीय प्रबन्धन सबसे अच्छा वही हो सकता है और सबसे अच्छा वित्त मंत्री वही हो सकता है जो भारत की बहुसंख्यक आबादी जो गांवों में रहती है, तो गावों की समस्या को देखने का प्रयास करे, और वही देश का सबसे अच्छा वित्त मंत्री हो सकता है। मुझे कहना है कि वर्तमान वित्त मंत्री ने उस चीज को देखने का प्रयास किया है कि भारत के गांव कहां हैं। मैं इस मायने में कह रहा हूं कि अब तक आजादी के बाद जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह एक सबसे अच्छा बजट इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, फूड एंड प्रौसैसिंग पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वर्षों की आजादी के बाद भी हम कृषि में कहां खड़े हैं, महोदय, इस बारे में आप बेहतर जानते हैं। भारत में यदि किसी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं, तो वह क्षेत्र अभी तक केवलमात्र कृषि का क्षेत्र है। यदि एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का काम किया जाएगा, तो भारत का उत्थान हो सकता है अन्यथा ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। हमारे देश में कृषि का क्षेत्र ही व्यापक है जहां बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं उसके अतिरिक्त हमें कोई और दूसरा ऐसा व्यापक क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। कृषि को उन्नत करने की आवश्यकता है और उसके लिए दो काम किए जाने जरूरी हैं- कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का काम और दूसरा वित्तीय प्रबन्धन इस ढंग से करने की जरूरत है कि कृषि पर से बोझ घटता चला जाए।

कृषि को लाभकारी, वैज्ञानिक ओर आधुनिक स्वरूप देने का काम भारत के बजट में जब होगा तब भारत की समस्याओं का निदान हो सकेगा क्योंकि बोझ पड़ता जा रहा है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि आज भारत के ऊपर वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई, वैज्ञानिक ढंग से खेती के प्रयोग, वैज्ञानिक ढंग से मोड ऑफ प्रोडेक्शन की बात हो तो शायद एक क्रांति हो सकती है।

मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि भारत के वित्त मंत्री सदन में मौजूद हैं। अभी हम लोगों का उपज पैदा करने का जो तरीका है, ढंग है, वह पुराना तरीका ही है। पुराने तौर तरीकों से ही हम चलने का प्रयास करते हैं। कभी भूमि टैस्टिंग का काम, भूमि की जांच करने का काम बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाये तो भारत की उपज को बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन स्वायत्त टैस्टिंग का काम बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, युद्ध स्तर पर नहीं हो रहा है। यदि सॉयल टैस्टिंग हो जाये तो किस भूमि पर कौन सी फसल ज्यादा हो सकती है और कारगर तरीके से उपजायी जा सकती है, वह पता चल सकता है इसलिए सॉयल टैस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ जमीन के प्रबंधन का भी सवाल है। कितनी भूमि हमने सिंचित एरिया में बदलने का काम किया है और कितना पैसा गलत ढंग से बर्बाद हुआ है, उस सिस्टम को आज देखने की जरूरत है। आज बिहार में जितनी भूमि में सिंचाई की बात की गई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी सिंचित भूमि का दावा बिहार में किया गया है, क्या उतनी भूमि सिंचाई हो जाती है? चाहे पूर्णिया का इलाका हो चाहे भोजपुर रोहतास का इलाका। जितनी भूमि सिंचित दिखाई गई है क्या वह सिंचित भूमि है, क्या उतनी भूमि में फसल ली जा सकती है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार की नौ सिंचाई परियोजनायें ये रोके हुए हैं इसलिए आप उनको बोलिये।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह (बिक्रमगंज): आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जितने उच्च स्वर में आप कह रहे हैं, जब आप पटना की धरती पर उतरें तो उतने ही उच्च स्वर में वहां भी इस मामले को रखें। यह मेरी आपसे मीनिमम अपेक्षा है। कि जहां तक सिंचाई की बड़ी योजनाओं की बात है, वे पूरी तरह से सफल नहीं हुई हैं। मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए । लघु सिंचाई योजनाओं को क़ियान्वित किया जाए तब सिंचाई की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सकती है और भारत की उपज भी बढ़ सकती है। आज बिहार में जितनी खाद की खपत होती है, उससे दुगुनी खाद की खपत उत्तर प्रदेश में हो रही है, हरियाणा और पंजाब की बात तो छोड़ दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : खाद के कारखानों को यह पैसा नहीं दे रहे हैं।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : खाद के कारखानों की बात आपने सही उठाई है। श्री यशवंत सिन्हा जी से मैं जरूर कहूंगा, इससे रघुवंश प्रसाद जी भी खुश हो जायेंगे, कि कहीं आप उदार बनने के चक्कर में और भारत की वित्तीय स्थिति को देखने में कहीं आप अपने राज्य के प्रति अनुदार न हो जायें, इसका ख्याल बराबर करते रहें, यह मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि सिंदरी बरौनी की हालत खराबहो गया

.....(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सिंदरी को इन्होंने रोक रखा है।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : सिंदरी के बारे में मैंने अभी कहा है। आप जरा थोड़ा सा एटेंटिव रहिये। अगर मैं कोई बात भूल जाऊं तो उसे आप याद दिला दीजिए। ... (व्यवधान) मुझे एक बात कहनी है कि सिंचाई व्यवस्था को ऐसे राज्यों में दुरस्त करने की जरूरत है जो राज्य भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने के बाद सिंचाई की असुविधा के कारण उतनी पैदावार नहीं दे पा रहे हैं जैसी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि। आज इस ढंग की नीति बनानी पड़ेगी कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य हैं, उनके लिए विशेष योजना बनानी चाहिए और जो समृद्ध राज्य हैं, उनके लिए एक अलग योजना हो तभी भारत का सम्पूर्ण विकास हो सकता है।

वित्त मंत्री जी के लिए यह बड़ी चुनौती है कि जो राज्य पिछड़े हैं, उनके लिए खास नीति अपनाई जाए। इस देश में अब वक्त आ गया है कि खर्च पर सीमा लगाने की बात बड़े पैमाने पर चलाई जाए। जब तक खर्च पर सीमा नहीं लगेगी, तब तक इस देश की समस्या का निदान नहीं हो सकता। दाम बांधने का सवाल मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन उठाया था। मैंने उस दिन कहा था और आज भी कह रहा हूं कि चाहे कारखाने का माल हो या कृषि का माल हो, एक समान नीति अपनाई जाए, मूल्य में असमान अंतर नहीं हो तभी इस देश में सुधार हो सकते है। आज हमें ऐसी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है।

कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे मितव्ययिता की बात, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ने उसे उठाया है, चूंकि वित्त मंत्री जी ने राजकोषीय और राजस्व घाटे की बात कही है, यह केवल भारत के वित्त मंत्री के प्रयास से ही संभव नहीं है, इसके लिए नीति बन सकती है, इसमें राज्यों को भी सहयोग करना पड़ेगा और जब तक राज्य सहयोग नहीं करेंगे तब तक इसका निपटारा नहीं हो सकता। चाहे राज्य स्तर पर हो या केन्द्र स्तर पर हो, व्यवस्थागत खर्च बहुत बढ़ता चला गया है। देश को बचाने के लिए इन सवालों पर सभी ओर से गंभीरता से विचार होना चाहिए तभी देश संभल सकता है और देश को बचाया जा सकता है।

आज बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है। बेरोजगारों के लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उससे और ज्यादा कठोर नीति अपनानी पड़ेगी क्योंकि अब भारत के वित्त मंत्री के सामने सवाल उपस्थित होगा कि जिन्होंने ऋण लिया है, उनसे वसूली कैसे की जाये। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है जो बेरोजगारो के लिए नीति बनी है, उसके कार्यान्वयन का सवाल है। हम आज वित्त मंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं और वह इसकी फीजीबिलिटी पर अवश्य विचार करने की कोशिश करेंगे कि आप हर राज्य में सौ ऐसे स्थान चुनें जहां उस स्थानों को प्रतीक माना जाए, जहां रोड का विकास, बेरोजगारी निवारण, पानी के प्रबंधन का विकास पूर्ण रूप से हो समग्र विकास की योजना बने। आपको सहायता के लिए राज्य सरकारों की जरूरत पड़ेगी, शायद वे सौ प्रतीक स्थान उस राज्य के विकास के लिए एक कड़ी का काम करेंगे, एक आदर्श स्थापित करने का काम करेंगे। इस पर आप विचार करेंगे, यह मेरा आग्रह और निवेदन है।

सभापति महोदय, आपकी घंटी बज रही है और मैं समझता हूं कि अब मुझे ज्यादा देर न करके अपनी बात समाप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी मुल्क जिस हालत में है, भ्रष्टाचार एक बड़ा सवाल बन गया है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये राज्य और केन्द्र स्तर पर सहमति बननी चाहिये और जो लोग आर्थिक मामलों के अपराधी हैं, जब तक उनको जेलों में नहीं डाला जाएगा तब तक देश की व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक और कठोर कदम उठाने की जरूरत है तभी देश सुधर सकता है क्योंकि देश ऋण में डूब गया है।

मैं चाहूंगा कि भारत के वित्त मंत्री जी लघु उद्योगों के विस्तार की तरफ जरूर ध्यान दें। यदि आप एक बड़ा उद्योग खड़ा करेंगे, उसमें आपको जितना रोजगार मिल सकता है। माना कि दस व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, यदि उतने ही पैसे से आप मध्यम श्रेणी के उद्योग खड़ा करेंगे तो ३० प्रतिशत अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है और उतना ही पैसा यदि लघु उद्योग इकाइयों में लगायेंगे तो ९० प्रतिशत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब नीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है कि लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। अब नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है कि मध्यम उद्योग का भी विस्तार किया जाए।

20.00 hrs.

अब जरूरत है कि गांव-गांव की बिजली की व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाये। आजकल तो लगता है कि बिजली की विभाग की परिभाषा बदल गई है। मैं कमेटी में हूं, मैंने पूछा कि बिहार के कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है तो जो जवाब आया, उससे वास्तव में हजारों गांवों में विद्युतीकरण कम हुआ है। रिपोर्ट आ गई और यदि कहा जाये कि यह भी एक बड़ा स्कैंडल है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। विचित्र तर्क दिया गया कि गांव में अभी केवल पोल गड़ा है और विद्युतीकरण की रिपोर्ट दे दी गई है। बिहार से जो रिपोर्ट आई है वह आश्चर्यजनक है। यदि आज गांवों का पता लगाया जाये तो हजारों गांव ऐसे हैं, जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि हजारों गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ लेकिन दावा कर दिया गया है उतने गांवों में वह पैसा कहां गया? यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। बिजली और रोजगार एक दूसरे से जुडे हैं मैं चाहूंगा कि छोटे रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया जाये, जिससे रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके, यदि ऐसा हुआ तो हिंसात्मक गतिविधियां, जो देश के पैमाने पर और राज्यों के स्तर पर फैल रही हैं, उसका और विस्तार होगा। उसमें रोजगार के अभाव में घूमने वाले नौजवानों की भी बड़ी संख्या है।

अन्त में एक सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करके और भारत के वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, वह प्रवासी मजदूरों की सवाल है। मुझे लगता है कि बजट में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर विचार

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, the time is 8.00 p.m. Many hon. Members want to speak on this subject. Is the sense of the House to extend the time beyond 8.00 p.m.?

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): We have agreed to sit up to 8.00 p.m. We will adjourn. We will continue tomorrow.

SHRI CHETAN CHAUHAN (AMROHA): Let him complete, then the House may be adjourned.

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि दिल्ली में एक न्यूज आई है कि बड़ी संख्या में बिहारी लोग रह रहे हैं और उस संख्या के चलते यहां गंदगी बढ़ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली, बिहार और भारत के अन्य प्रदेशों के गरीबों से घिरता जा रहा है। दिल्ली को इतना बेखबर नहीं रहना चाहिए कि वह क्यों घिरती जा रही है, यदि उन राज्यों में रोजगार के अवसर रहते तो दिल्ली में आने वाले लोगों की संख्या इस अनुपात में नहीं बढ़ती, इसलिए इस सवाल पर कल्याणकारी कदम उठाने के लिए, उनको कानूनी संरक्षण देने के लिए और उनको नये ढंग से राहत पहुंचाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन लोगों को लगे कि हमारे प्रोटैक्शन में भी भारत का लॉ खड़ा है, हम निराश्रित नहीं हैं, हमारी रक्षा होगी। बस इतनी ही बात कहकर इस बजट के समर्थन में अपनी बात रखकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI KONIJETI ROSAIAH :We have agreed to sit up to 8.00 p.m. But let us continue.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): आप हमारा नाम पुकार दें, हम कल शुरू कर देंगे।

MR. CHAIRMAN: When I asked for the sense of the House for extension, nobody agreed. I have no objection if the hon. Members agree to sit beyond 8.00 p.m. We can continue for one more hour.

... (Interruptions)

MR.CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 16th March, 1999 at 11.00 a.m.

2009 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Tuesday, March 16, 1999/Phalguna 25, 1920 (Saka).

>श्री शांता कुमार (कांगड़ा): सभापति महोदय, इस वर्ष के जनरल बजट पर बोलते हुये विपक्ष की ओर से डा. बलराम जाखड़ ने बहुत कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने पूरा बजट पढ़ा नहीं या इसमें अन्तर्निहित अच्छी बातों का उल्लेख करने में संकोच किया है। मैं समझता हूं कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रकाश में रखते हुये इस बार का बजट बहुत सोचकर विचार करके प्रस्तुत किया गया है।

सभापति जी, डा. बलराम जाखड़ मुख्य बातों में से बेरोजगारी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा, उससे कुछ सहमत जरूर हूं लेकिन यह परिस्थिति पिछले ११-१२ महीनों का नतीजा नहीं है। यह सब कुछ पिछले ५० सालों की नीति का परिणाम है। इसलिये जर्जर होती विरासत में मिली आर्थिक परिस्थिति में जिस बजट को बनाया गया है, वह सरकार ने सराहनीय काम किया है। इस के लिये मैं ि वत्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, इस बजट में जो मूल बातें हैं, उन सब में मुख्य बात यह है कि विकास कार्यों में जनता को जोड़ने की कोशिश की गई है। किसानों, मजदूरों और ग्राम सभाओं को विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। यह पहला मौका है कि केन्द्र सरकार सीधे-सीधे ग्रामसभाओं पर विश्वास करेगी और उन्हें धन देगी। ि वकास की सारी जिम्मेदारी ग्रामसभाओं पर दी जायेगी। इसमें ग्रामसभा वर्ष मनाने की बात कही गई है, कर-ढांचे को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है और उसे पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम के अंदर विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इक्ट्ठा किया गया है।

जो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत चलते थे, उन्हें स्ट्रीमलाइन करने की, उन्हें कंसॉलिडेट करने की कोशिश इस बजट में की गई है। मैं आदरणीय जाखड़ जी से निवेदन करूंगा कि यह स्वतंत्र भारत का पहला बजट है जिसमें गांव का, किसान का, गरीब का ध्यान रखा गया है। जब से ग्लोबलाइज़ेशन शुरू हुआ, जब से ि वदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आईं, तब से गांव पूरी तरह से उपेक्षित हो गए थे। पहली बार उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई है। सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने का एक शुभारंभ इस बजट में किया गया है। देश का घाटा १,०४,००० करोड़ रुपये तक बढ़ गया था, उसे ७९,००० करोड़ रुपये पर लाकर २४,००० करोड़ रुपये घटाने का भी प्रयत्न इस बजट में किया गया है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में इससे और अच्छे तरीके से बजट पेश नहीं किया जा सकता था। इसमें गांव की, गरीब की, किसान की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में बहुत सोच-समझकर कुछ नये कार्यक्रम सामने लाए गए हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पानी चाहिए। इस दृष्टि से जल विकास कार्यक्रमों को इकट्ठा किया गया है। शायद यह बात आदरणीय जाखड़ जी के ध्यान में नहीं आई। बहुत से कार्यक्रम जल के संबंध में, सिंचाई के संबंध में अलग-अलग तरीके से चलते हैं और अलग-अलग तरीके से चलने के कारण उसका ठीक लाभ गांवों में नहीं पहुंच पाता। यह सोची समझी दूरदर्शी योजना इस बजट में है कि जल विकास के जितने कार्यक्रम हैं, उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जल विकास का बनाया है। उसके लिए धन का प्रावधान भी केन्द्र सरकार की तरफ से किया गया है।

दूसरी बात, वॉटर शैड डेवलपमेंट फंड भी माननीय जाखड़ जी के ध्यान में नहीं आया। इसमेंकेन्द्र की सहायता होगी और तीन साल के अंदर १०० प्रायॉरिटी जिलों के अंदर वॉटर शैड डैवलपमेंट फंड द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे। इससे सिंचाई को एक नयी दिशा मिलेगी। सभापति जी, जाखड़ जी ने ठीक कहा कि इस देश में भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण सब्जियां और फल नष्ट होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक प्रतिवर्ष १६००० करोड़ रुपये या इससे ज्यादा -- शायद २५,००० करोड़ रुपये के फल और सब्जियां नष्ट होती हैं क्योंकि रख-रखाव का इंतजाम नहीं है। लेकिन माननीय जाखड़ जी, आपने बजट की ओर ध्यान नहीं दिया। भंडारण सुविधाओं के लिए कैपिटल सब्सिडी की स्कीम इस बजट में रखी गई है। १२ लाख टन भंडारण की व्यवस्था करने का लक्षय तय किया गया है। साढ़े चार लाख टन प्याज के भंडारण की व्यवस्था करने का लक्षय रखा गया है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि भंडारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट में रखने की कोशिश की गई है। २० लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय हुआ है जिसमें से छः लाख दिये जा चुके हैं। इस से भी किसान को फायदा होगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है, यह कार्यक्रम भी किसानों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

चौथी बात किसान, गांव और गरीब के लिए आर.आई.डी.एफ. -- रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की है। इसे ३००० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ३५०० करोड़ रुपये किया गया है और उसकी अदायगी पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई है। क्या यह गांवों के लिए नहीं है? क्या यह गांवों की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए नहीं है? मैं बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूं कि गांवों की दिशा में स्वतंत्र भारत में किसी बजट में कभी इतना अधिक नहीं सोचा गया जितना अधिक इस बार के बजट में सोचा गया है। वॉटर यूज़र्स ऐसोसिएशन को प्रबंध सब्सिडी देने की बात पहली बार इस बजट में कही गई है ताकि जल का उपयोग करने वाले जो संगठन गांवों में हैं, उनके प्रबंध के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाए।

उनका काम बढ़े, उनका कार्यक्षेत्र बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को १६८ करोड़ रूपये का अधिक प्रावधान इसी बजट में रखा गया है। कृषि परियोजना व्यय ३५ प्रतिशत बढ़ाया गया है। बलराम जाखड़ जी अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्हें ३५ प्रतिशत बढ़ी हुई फीगर इसमें मिलेगी। इसके अतिरिक्त गांवों में रहने वाले बेसहारा लोगों का भी भी ध्यान बजट में रखा गया है। इसमें अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ऐसे गरीब बूढ़े, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको मासिक दस किलों अनाज मुफ्त देने की घोषणा इस बजट में की गई है। सभापति महोदय, गांवों में रहने वाले लोग सच्चा भारत है। उनकी अनपढ़ता को दूर करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम एजूकेशन गारंटी स्कीम इस बजट में शुरू किया गया है, जिसके तहत एक लाख आठ हजार प्राथमिक स्कूल इस पंचवर्षीय योजना में खोले जायेंगे। गांवो की निरक्षरता दूर होगी, शिक्षा आयेगी, तभी गांव बाकी देश के मुकाबले आयेंगे। यह बात भी आपके ध्यान में नहीं आई। नोबल पुरस्कार विजेता श्री अमर्तय सेन ने बड़े जोर से यह बात कही कि भारत ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि जो मूल स्रोत विकास का है मानव, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसमें पैसा नहीं लगाया और मैं समझता हूं कि बजट की सारी बातें जो मैं गिना रहा हूं वे गावों के लिए, गरीब के लिए और आम आदमी के लिए हैं। एजूकेशन गारंटी स्कीम के द्वारा एक लाख आठ हजार नये प्राथमिक स्कूल खोल करके गांवों की अनपढ़ता को दूर किया जायेगा।

सभापति महोदय, ग्रामीण समृद्धि योजना - इसमें ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है। हमने लोकतंत्र का आदर किया है, गांवों का आदर किया है, गावों के चुने हुए लोगों को अधिकार दिया है, उन पर नया विश्वास प्रकट किया है। ग्राम समृद्धि योजना में गांवों की पंचायत को स्वरोजगार की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है उनको विश्वास में लिया गया है और इसके लिए धन का प्रावधान किया जायेगा। समग्र आवास योजना में केवल आज आवास ही नहीं, आवास, सफाई व पानी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में गरीब लोगों का विकास करने की बात कही गई है।

सभापति महोदय, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - इसमें भी गावों के गरीब लोगों को स्वरोजगार के कार्यक्रमों को स्वयं संचालित करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह डीसैण्ट्रलाइजेशन की दिशा नहीं, यह महात्मा गांधी जी का सपना था। एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी कार्यक्रम इस बजट में रखा गया है। आपने उद्योगों की बात कही कि गावों में उद्योगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि बजट को दोबारा पढ़ने की कृपा करिये, इसमें यह निर्णय किया गया है कि प्रतिवर्ष सौ ग्राम उद्योग समूह सुस्थापित किये जायेंगे। ग्रामों में उद्योग समूह, सौ क्लस्टर इंडसट्रियल, रूरल स्थापित करने का निर्णय इस बजट में किया गया है। इससे सीधे औद्योगीकरण की प्रक्रिया गतिशील होगी। गावों के लिए पहली बार इतना अधिक धन, गावों में पहली बार इतनी अधिक योजनाएं, इससे गावों की तरफ जो धन जायेगा तो विकास बढ़ेगा, स्वरोजगार की सारी की सारी कल्पनाएं वहां साकार होंगी। सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जब मैंने यह सारा बजट पढ़ा तो मुझे राष्ट्र कवि सोहन लाल जी की वह बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था - 'है सच्चा हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में', इसमें गावों के बारे में पहली बार चिंता हुई है, आपको इस चिंता को एप्रीशिएट करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बजट गांव प्रधान है। यह गावों के गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और सही अर्थों में यह स्वतंत्र भारत का पहला अंत्योदय बजट है। पीछे रह गये गांवों के लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त बजट में और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं लेकिन मैं उनमें से कुछ बातों का जिक्र करूंगा। इसमें गोल्ड बॉण्ड की जो स्कीम है यह इन्नोवेटिव है, कल्पनाशील है, बहुत रचनात्मक है। इस देश के लोगों में सोना रखने की इच्छा है, आदत है और सोना लोगों के पास घरों में भी पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, उसका कोई उपयोग नहीं होता, तनाव रहता है, चोरियां होती हैं, संभालना पड़ता है। इसलिए यह बहुत सोची-समझी और देश के हित की योजना बनाई गई है। १९९८-९९ में ६१४ टन यानी लगभग छः लाख किलो सोना आयात किया गया जिस पर भारत को ५-६ हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी। इससे क्या होगा लोगों के पास जो सोना पड़ा है वह बैंकों में रखने को प्रोत्साहन मिलेगा और उससे सरकार को सोना आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि योजना सफल होगी, तो ५-६ हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी और सरकार को केवल ४ प्रतिशत पर विकास के लिए साधन मिलेंगे। सरकार केवल ४ प्रतिशत ब्याज देगी। इतने ब्याज पर कभी भी और कहीं से धन प्राप्त नहीं हो सकता। सरकार को हजारों करोड़ रुपए केवल ४ प्रतिशत ब्याज पर मिलेंगे और देश की जनता को अपना सोना बैंक में रखने की सुविधा मिलेगी जिस पर चार प्रतिशत ब्याज कमाने का अवसर मिलेगा। इससे बढ़िया और रचनात्मक योजना मैं समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकती। यह योजना, बांडस, स्माल सेविंग्स और म्युचुअल फंड की योजनाओं से भी अच्छी योजना है। मैं समझता हूं कि यह सोच-समझ कर, कल्पनाशील और सराहनीय योजना है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी पर हम सभी ने चिन्ता प्रकट की है। स्वाभाविक है कि उस दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं इस सदन का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि सरकार अपने खर्च को कम करने पर गंभीर कदम उठाएगी। यह खाली वायदा नहीं है बल्कि इसे बराबर लागू किया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा है सबसिडी के प्रश्न पर पूरे सदन में एक सहमति बनाई जानी चाहिए। वास्तव में जिन गरीबों को इसकी जरूरत है, उन्हें सबसिडी दी जाए, लेकिन जहां अनावश्यक है, वह समाप्त की जाए। इन दोनों दिशाओं में कोशिश की है और इस बजट में सरकारी खर्च को घटाने की कोशिश की गई है। जितनी भी सबसिडी इस देश में दी जाती है उसमें से ज्यादातर की आवश्यकता नहीं है। हर प्रदेश की सरकार और हम यहां पर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में पैसा बढ़ाकर दिया जाए, उस क्षेत्र में पैसा बढ़ाकर दिया जाए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह पैसा आएगा कहां से? मेरा निवेदन है कि पैसा बढ़ाने की बात करने वाले मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि वह पैसा आएगा कहां से।

सभापति महोदय, सबसिड़ी पर आज हम १ करोड़ ४० लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है इस पर एक सहमति बने कि कौन सी सबसिडी आवश्यक है और कौन सी आवश्यक नहीं है। महोदय, सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण किया गया था और उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि बहुत सी सबसिडी ऐसी हैं जिनको समाप्त किया जा सकता है। इस पर सहमति बने तो पैसा बचे। मैं गवर्नमेंट के डिसकशन पेपर से उस रिपोर्ट के उस हिस्से को पढ़ना चाहता हूं जिसमें सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिए गए हैं-

" Even in the case of subsidy on a final good, food, targeting is reported to be poor, and leakage extensive. Similarly, on average, nearly half of the fertiliser subsidies is estimated to accrue to the producers/suppliers rather than the farmers. A significant portion of subsidies in higher education is appropriated by the middle to high income groups, because shortages of seats in this sector are cleared by a quality-based screening in the shape of entrance examination, interview, group discussions, etc., where the poorer sections of society are easily competed out. Health subsidies exhibit a non-rural and pro-rich bias. Thus our subsidy regime is not tangibly progressive."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सरकार ने कुछ सबसिडी कम की जिस पर हमारे मित्रों ने शोर मचाया, गैस पर सबसिडी कम की गई, तो शोर मचाया और कहा कि गैस पर सबसिडी कम करने से गरीबों को नुकसान हुआ।

मैं समझता हूं कि आज जरा इस देश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें कि देश का गरीब कैसे रोटी बनाता है?